



रोमारियो ने बनाया इतिहास
लगाई हैट्रिक

Page-04



सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

Shahid Kapoor की Farzi 2
सीक्वल के लिए मिली
45 करोड़ की फीस

Page-05



मुंबई को मिली नई मेयर रितु तावड़े संभालेंगी कमान, संजय घाड़ी बने डिप्टी मेयर

महत्वपूर्ण बिंदु:

- भाजपा की रितु तावड़े मुंबई की नई मेयर बनेंगी।
- शिवसेना (शिंदे गुट) के संजय घाड़ी डिप्टी मेयर पद संभालेंगे।
- गठबंधन की सहमति के बाद दोनों नामों पर अंतिम निर्णय हुआ।
- बीएमसी देश की सबसे समृद्ध नगर निकाय संस्था मानी जाती है।
- जलभराव, सड़कों के गड्ढे, ट्रैफिक और कचरा प्रबंधन प्रमुख चुनौतियां रहेंगी।
- इस फैसले का आगामी नगर निकाय चुनावों पर भी असर पड़ सकता है।

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सियासत में बड़ा फैसला सामने आया है। मुंबई महानगरपालिका (BMC) में महापौर पद के लिए भाजपा की रितु तावड़े के नाम पर सहमति बन गई है, जबकि उपमहापौर पद पर शिवसेना (शिंदे गुट) के संजय घाड़ी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लंबे समय से चल रही बैठकों, समीकरणों और राजनीतिक मंथन के बाद गठबंधन ने इन दोनों नामों पर अंतिम मुहर लगाई, जिससे नगर निगम की सत्ता संरचना स्पष्ट हो गई है। बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निकाय संस्था मानी जाती है और इसका वार्षिक बजट कई राज्यों के बजट के बराबर माना जाता है। ऐसे में महापौर और उपमहापौर पद का राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व काफी बढ़ जाता है। माना जा रहा है कि भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) के बीच यह समझौता महानगरपालिका में स्थिर प्रशासन सुनिश्चित करने और विकास परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से किया गया है। रितु तावड़े के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुंबई की बुनियादी समस्याओं को सुलझाने की होगी। हर साल बारिश के दौरान जलभराव, गड्ढों से भरी सड़कें, ट्रैफिक जाम, कचरा प्रबंधन और झुग्गी पुनर्विकास जैसे मुद्दे शहर के लिए बड़ी परेशानी बने रहते हैं। नागरिक लंबे समय से इन समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग करते रहे हैं। नई मेयर से उम्मीद की जा रही है कि वह प्रशासनिक स्तर पर सख्त फैसले लेकर व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करेंगी। दूसरी ओर डिप्टी मेयर बनने जा रहे संजय घाड़ी की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वे निगम के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने, सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने और राजनीतिक स्तर पर गठबंधन में तालमेल बनाए रखने का काम करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की संयुक्त कार्यशैली आने वाले समय में बीएमसी की कार्यप्रणाली पर सीधा असर डालेगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह नियुक्ति केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी अहम है। इससे महानगरपालिका में सत्तारूढ़ गठबंधन की पकड़ मजबूत होगी और आगामी चुनावी समीकरणों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। विपक्ष ने हालांकि इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि असली परीक्षा अब कामकाज की होगी और जनता को केवल घोषणाओं नहीं बल्कि जमीन पर बदलाव चाहिए। मुंबई के नागरिकों की नजर अब नई नेतृत्व टीम पर टिकी है। बुनियादी सुविधाओं में सुधार, तटीय सड़क परियोजना, मेट्रो विस्तार, प्रदूषण नियंत्रण और डिजिटल सेवाओं के विस्तार जैसे मुद्दों पर ठोस प्रगति ही इस नई टीम की सफलता तय करेगी। नई नेतृत्व टीम के सामने वित्तीय प्रबंधन भी एक अहम परीक्षा होगी। बीएमसी का बड़ा बजट होने के बावजूद कई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पातीं, जिससे लागत बढ़ जाती है और नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे में पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया की निगरानी और कार्यों की समयबद्धता पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही डिजिटल सेवाओं को बढ़ाकर प्रॉपर्टी टैक्स, शिकायत निवारण और ऑनलाइन अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल बनाना भी प्राथमिकता माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रशासनिक फैसले तेज और जवाबदेह रहे, तो आने वाले महीनों में शहर की मूलभूत सुविधाओं में वास्तविक सुधार देखने को मिल सकता है और नागरिकों का भरोसा भी मजबूत होगा। इसके अलावा स्वच्छता अभियान, हरित क्षेत्रों के विस्तार और तटीय इलाकों में बाढ़ सुरक्षा व्यवस्था को भी प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है।



तबीयत बिगड़ने से पप्पू यादव अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी

जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और सांसद पप्पू यादव की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार उन्हें बेचैनी और कमजोरी की शिकायत होने पर पहले स्थानीय चिकित्सकों को दिखाया गया, जिसके बाद एहतियातन उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों की टीम ने प्राथमिक जांच के बाद बताया कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। आवश्यक मेडिकल टेस्ट कराए जा रहे हैं ताकि बीमारी के सही कारण का पता लगाया जा सके। अस्पताल प्रशासन के अनुसार चिंता की कोई गंभीर बात सामने नहीं आई है, लेकिन उन्हें कुछ समय तक आराम और चिकित्सकीय देखरेख की जरूरत होगी। जैसे ही पप्पू यादव के अस्वस्थ होने की खबर फैली, उनके

समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर पहुंचने लगे। पार्टी नेताओं ने समर्थकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरों की सलाह के बाद उनके आगामी कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। चिकित्सकों ने उन्हें पूरी तरह आराम करने और सार्वजनिक गतिविधियों से कुछ समय दूर रहने की सलाह दी है।



आज ओला-उबर-रैपिडो सेवाएं प्रभावित – ड्राइवरों की हड़ताल से यात्रियों को परेशानी

ऐप आधारित कैब सेवाओं ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े ड्राइवरों ने आज विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल का ऐलान किया है, जिसका असर कई शहरों में साफ दिखाई दे रहा है। सुबह से ही यात्रियों को कैब बुक करने में कठिनाई हो रही है और जहां गाड़ियां उपलब्ध हैं वहां किराया सामान्य दिनों की तुलना में अधिक दिखाई दे रहा है। ड्राइवर संगठनों का कहना है कि बढ़ते ईंधन दाम, कंपनी द्वारा बढ़ाया गया कमीशन और इंसेंटिव में कटौती के कारण उनकी आय लगातार घट रही है। उनका आरोप है कि ऐप कंपनियों किराया बढ़ा देती हैं लेकिन उसका लाभ ड्राइवरों तक नहीं पहुंचता। इसके अलावा कुछ ड्राइवरों ने प्रति किलोमीटर न्यूनतम किराया तय करने, कमीशन घटाने और दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं लागू करने की भी मांग उठाई है। हड़ताल के कारण ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और



एयरपोर्ट-रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को ऑटो या निजी साधनों का सहारा लेना पड़ा, वहीं कुछ जगहों पर बसों और लोकल परिवहन में भीड़ बढ़ गई। पीक आवर्स में किराए में सर्ज प्राइसिंग भी देखी गई।

बड़ी कूटनीतिक जीत: ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ हटाया, रूसी तेल आयात पर भी बनी सहमति

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान प्रशासनिक नेतृत्व में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई हालिया उच्च-स्तरीय वार्ता के बाद भारत-अमेरिका संबंधों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे व्यापारिक तनाव को कम करते हुए अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले कई उत्पादों पर लगाया गया 25% टैरिफ हटाने की घोषणा की है। इस फैसले को नई दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय स्टील, एल्युमिनियम और कुछ इंजीनियरिंग उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। भारतीय उद्योग संगठनों का दावा था कि इससे छोटे और मध्यम निर्यातक विशेष रूप से प्रभावित हुए और अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया। अब टैरिफ हटाने से भारतीय उत्पादों की कीमत अमेरिका में कम होगी और निर्यात में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, इस समझौते में ऊर्जा सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा रहा। अमेरिका लंबे समय से चाहता था कि भारत रूस से तेल खरीद कम करे, जबकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के कारण सस्ती दरों पर रूसी कच्चे तेल का आयात जारी रखना चाहता था। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने एक मध्य मार्ग निकाला, जिसके तहत भारत ने पारदर्शी भुगतान तंत्र और अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप खरीद



सुनिश्चित करने पर सहमति दी, जबकि अमेरिका ने भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को समझते हुए कठोर प्रतिबंधात्मक रुख नरम कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करेगा। रक्षा, सेमीकंडक्टर सप्लाय चैन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी दोनों देशों ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। अमेरिका भारत को चीन के मुकाबले एक विश्वसनीय आर्थिक और सामरिक साझेदार के रूप में देख रहा है, वहीं भारत भी पश्चिमी तकनीक और निवेश को आकर्षित करना चाहता है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक टैरिफ हटाने से ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल, फार्मा इंटरमीडिएट्स और मशीनरी सेक्टर को तुरंत फायदा

होगा। खासकर एएमएसएमई सेक्टर के लिए यह राहत भरी खबर है क्योंकि इन उद्योगों का बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार पर निर्भर है। अनुमान है कि अगले एक वर्ष में भारत का अमेरिका को निर्यात कई अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। राजनीतिक स्तर पर भी इस समझौते के दूरगामी असर माने जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति मजबूत होगी और यह संकेत जाएगा कि भारत वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलन बनाकर अपने हित सुरक्षित कर सकता है। ऊर्जा और व्यापार दोनों मोर्चों पर संतुलित नीति अपनाकर भारत ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वह किसी एक धड़े में पूरी तरह शामिल हुए बिना बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है।

हिन्दी जगत महावंश
www.tvbharatvarsh.in

TV भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ई-पेपर
प्रदेश का नं. 1
प्रतिष्ठित हिन्दी न्यूज़
ई-पेपर

विज्ञापन दर

समय	दिनांक	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम
रेट	₹ 3000	₹ 6000	₹ 10,000	₹ 20,000	₹ 25,000	₹ 30,000	₹ 100000

8601780000

पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा से भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को नई गति

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मलेशिया यात्रा भारत-मलेशिया संबंधों और भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को नई मजबूती देने वाली है। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी, जिससे आसियान क्षेत्र में भारत की भूमिका और प्रभाव बढ़ने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी तीसरी मलेशिया यात्रा है। यह दौरा न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए, बल्कि भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस यात्रा के दौरान, वह अपने मलेशियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे। पीएम मोदी मलेशिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे, साथ ही व्यापारिक नेताओं और उद्योग प्रतिनिधियों से



भी मिलेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा 10वें भारत-मलेशिया सीईओ फोरम के साथ होगी। भारत और मलेशिया के बीच लंबे समय से संबंध हैं जो साझा इतिहास, संस्कृति और सम्यता में गहराई से जुड़े हुए हैं। ये संबंध मलेशिया में भारतीय प्रवासियों द्वारा और मजबूत होते हैं, जिनकी संख्या लगभग 2.9 मिलियन है, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भारतीय समुदाय बनाता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक राजनयिक और रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ भारत

के संबंधों को मजबूत करना है। यह मूल रूप से पहले की लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक विकसित रूप है, जिसे तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में अपनाया था। पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा से इस पहल को बड़ा बढ़ावा मिलने की संभावना है। पीएम मोदी के पद संभालने के बाद से दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ाना प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत को आसियान देशों से जोड़ने के लिए परिवहन, बुनियादी ढांचे और डिजिटल कनेक्टिविटी

(सड़कें, रेलवे, बंदरगाह और डिजिटल नेटवर्क) विकसित करने के लिए भी सक्रिय रूप से काम किया है। भारत और मलेशिया ने अगस्त 2024 में अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान, दोनों नेता इस साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे और भविष्य की प्राथमिकताएं तय करेंगे। चर्चा व्यापार और निवेश के विस्तार पर केंद्रित होगी, जिसमें भारत में मलेशियाई निवेश को प्रोत्साहित करना और गहरा आर्थिक सहयोग शामिल है। दोनों देश सेमीकंडक्टर के विकास में भी सहयोग कर सकते हैं।

बांग्लादेश में फिर सड़कों पर जनता का गुस्सा, प्रदर्शन तेज होते ही मोहम्मद यूनुस बैकफुट पर



बांग्लादेश की राजधानी ढाका एक बार फिर उबल पड़ी जब अंतरिम शासन के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। सैकड़ों कर्मचारी नौवां राष्ट्रीय वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे और तीखे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पेट में अन्न नहीं, विकास केवल बातों में है और अन्याय का हिसाब खून से होगा। शक्रवार सुबह लगभग साढ़े दस बजे शाहबाग क्षेत्र से जुलूस निकला और जामुना स्थित मुख सलाहकार आवास की ओर बढ़ा। रास्ते में कई जगह बैरिकेड लगाए गए, पर भीड़ ने धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश की। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा बलों ने पानी की बोछार, आंसू गैस और ध्वनि बम का सहारा लिया। इसके बावजूद कुछ समय के लिए प्रदर्शनकारी जामुना तक पहुंच गए। बाद में सुरक्षा कड़ी कर क्षेत्र खाली कराया गया। सबसे तीखे टकराव जामुना के बाहर हुए जहां कम से कम चालीस लोग घायल बताए गए। जब भीड़ ने बैरिकेड तोड़े तो लाठी चलानी पड़ी। इस विरोध में इंकिलाब मंच नाम का राजनीतिक समूह भी कूद पड़ा, जो यूनुस के विरोध के लिए पहले से जाना जाता है। उसके सह संस्थापक शरीफ उस्मान हादी की 18 दिसंबर को मौत हो गई थी, जिन्हें ढाका में सिर में गोली लगी थी। इंकिलाब मंच संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है और उसी मांग के साथ वह सरकारी कर्मचारियों के साथ जुड़ गया।



US Trade Deal पर पवन खेड़ा का तीखा हमला, बोले— 'यह समझौता नहीं, सरेंडर है'

व्यापार समझौता 'मेक इन इंडिया' को देगा मजबूती, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते (Interim Trade Agreement) को देश की आर्थिक प्रगति के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ बताया है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि यह समझौता न केवल व्यापारिक बाधाओं को कम करेगा, बल्कि भारत के जमीनी स्तर के उद्यमियों और कामगारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौता किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसर खोलकर 'मेक इन इंडिया' को मजबूत करेगा तथा महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेगा। प्रधानमंत्री ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद भी दिया। पीएम मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "भारत और अमेरिका के लिए बहुत अच्छी खबर। हमने दोनों महान देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा पर सहमति जताई है।" उन्होंने कहा कि यह रूपरेखा भारत-अमेरिका साझेदारी की बढ़ती गहराई, भरोसे और गतिशीलता को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा, "यह भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, लघु एवं मध्यम उद्योगों, स्टार्टअप नवोन्मेषकों, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर



खोलकर 'मेक इन इंडिया' को मजबूत करता है। इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा।" पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा यह रूपरेखा दोनों देशों के बीच निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को और गहरा करेगी। उन्होंने कहा कि यह रूपरेखा मजबूत और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला को भी मजबूत करेगी और वैश्विक वृद्धि में योगदान देगी। प्रधानमंत्री ने कहा, "जैसे-जैसे भारत विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम ऐसी वैश्विक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो भविष्य पर आधारित हों, हमारे लोगों को सशक्त बनाएं और साझा समृद्धि में योगदान दें।"

ताइवान के पास चीन की बड़ी सैन्य हलचल, PLA के 6 विमान देखे गए, सेना हाई अलर्ट पर

ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को सुबह 6 बजे (स्थानीय समय) तक अपने क्षेत्रीय जलक्षेत्र के आसपास छह चीनी विमानों और सात नौसैनिक जहाजों की मौजूदगी का पता लगाया। इन छह में से पांच विमान ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी रक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर गए। X पर एक पोस्ट में, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आज सुबह 6 बजे (UTC+8) तक ताइवान के आसपास PLA के 6 विमानों और PLAN के 7 जहाजों का पता चला। इनमें से 5 विमान ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी रक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर गए। हमने स्थिति पर नजर रखी और कार्रवाई की। इससे पहले शुक्रवार को, रक्षा मंत्रालय ने PLA के 8 विमानों और PLAN के 6 जहाजों का पता लगाया था। इनमें से 6 विमान मध्य रेखा पार करके ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी रक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर गए। X पर एक पोस्ट में, रक्षा मंत्रालय ने कहा, "आज सुबह 6 बजे (UTC+8) तक ताइवान के आसपास PLA के 8 विमानों और PLAN के 6 जहाजों का पता चला। इनमें से 6



विमानों ने मध्य रेखा पार की और ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया। हमने स्थिति पर नजर रखी और जवाबी कार्रवाई की।" बुधवार को जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों पर कई देशों की बैठक बुलाई, जिसे चीन के लगभग प्रभुत्व से खुद को बचाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की। ट्रंप ने टुथ सोशल पर एक पोस्ट में शी जिनपिंग के साथ अपनी बातचीत का जिक्र किया, अप्रैल में चीन की अपनी यात्रा की पुष्टि की और कहा कि चीन के साथ संबंध बेहद अच्छे हैं।

पीयूष गोयल ने बताया USA Trade Deal का असर, नियति पर अब Zero Duty,

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते की सराहना की। समझौते का विवरण देते हुए गोयल ने कहा कि अब अमेरिका निर्यात के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य होगा और भारतीय व्यापारियों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत दोनों देशों का मुख्य लक्ष्य 500 अरब डॉलर का वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार हासिल करना है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र इस समझौते से खुश है और सरकार को हर तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। पीयूष गोयल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में भारत की यात्रा में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है... भविष्य को ध्यान में रखते हुए, और दोनों देशों के संबंधों, राजनयिक संबंधों और उनके नेताओं के बीच मित्रता को देखते हुए, द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा फरवरी 2025 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रतिवर्ष 500 अरब

डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हासिल करना था। आज का दिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पूरे देश में खुशी की लहर है। देश के हर क्षेत्र में भविष्य को लेकर जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में नए अवसर खुलेंगे, और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लगभग तीस खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका अब हमारे निर्यातकों के लिए सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करके अपने दरवाजे खोलेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों के हितों की रक्षा जिस तरह से की गई है, उससे किसानों और डेयरी क्षेत्र दोनों के हितों की रक्षा हुई है। उन्होंने कहा कि अब कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर हमारे निर्यातकों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को माल भेजने पर शून्य शुल्क लगेगा। उदाहरण के लिए, रत्नों और हीरों पर शून्य शुल्क लागू होगा। भारत से बड़ी मात्रा में निर्यात किए जाने वाले औषधीय उत्पादों पर भी शून्य शुल्क



लगेगा। भारत से अमेरिका को बड़ी संख्या में निर्यात किए जाने वाले स्मार्टफोन पर भी शून्य शुल्क जारी रहेगा। इस प्रकार, भविष्य में ऐसी कई वस्तुएं हैं जिन पर शून्य शुल्क लगेगा। कृषि क्षेत्र में भी, भारत से अमेरिका को निर्यात की जाने वाली कई वस्तुओं पर शून्य पारस्परिक शुल्क लागू होगा, यानी अतिरिक्त शुल्क शून्य होगा। उदाहरण के लिए, मसाले, चाय, कॉफी और उनसे बने उत्पाद, नारियल और नारियल तेल, वनस्पति मोम, सुपारी, ब्राजील नट, काजू और शाहबलूता। कई फल और सब्जियां भी इसमें शामिल हैं।



संपादक की कलम से

आतंकी हमलों के बाद अक्सर चर्चा सुरक्षा चूक, खुफिया नाकामी या सीमा पार साजिशों तक सीमित रह जाती है, लेकिन एक सवाल बार-बार अनदेखा कर दिया जाता है—आखिर आतंकवाद के लिए मानव बम तैयार कैसे होते हैं? बंदूक थामने वाला हाथ अक्सर किसी युवा का होता है, जिसके सपनों, गुस्से और असंतोष का इस्तेमाल कर उसे हिंसा के रास्ते पर धकेल दिया जाता है। आतंकवाद की सबसे खतरनाक सच्चाई यही है कि यह युवाओं की सोच को ज़हर देकर अपनी फैक्ट्री तैयार करता है। आज का आतंकवाद सिर्फ जंगलों या सीमावर्ती इलाकों में नहीं पनपता, बल्कि मोबाइल स्क्रीन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एन्क्रिप्टेड चैट्स के जरिये युवाओं के दिमाग में घर कर रहा है। यह एक साइलेंट प्रोसेस है, जो बिना शोर किए समाज की जड़ों को खोखला करता है। अधिकांश युवा जो आतंकवादी संगठनों के जाल में फंसते हैं, वे जन्म से अपराधी नहीं होते। बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव, पहचान का संकट, राजनीतिक हताशा और निजी असफलताएं—ये सभी कारक उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर बनाते हैं। आतंकी संगठन इसी कमजोर मानसिक अवस्था का फायदा उठाते हैं। वे युवाओं को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी पेशानियों की जड़ कोई एक समुदाय, सरकार या देश है। झूठे वीडियो, तोड़े-मरोड़े गए इतिहास और भावनात्मक भाषणों के जरिये नफरत को “न्याय” का नाम दे दिया जाता है। धीरे-धीरे युवा यह मानने लगता है कि हिंसा ही समाधान है। आधुनिक आतंकवाद का सबसे खतरनाक हथियार अब AK-47 नहीं, बल्कि स्मार्टफोन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद कट्टरपंथी कंटेंट, फेक न्यूज और प्रोपेगंडा वीडियो युवाओं को तेजी से प्रभावित करते हैं। एल्गोरिदम आधारित प्लेटफॉर्म एक बार किसी यूजर को कट्टर कंटेंट दिखाना शुरू कर दें, तो वह उसी विचारधारा के “इको चैंबर” में फंस जाता है। आतंकी संगठन अब भर्ती के लिए मदरसों या ट्रेनिंग कैंपों पर निर्भर नहीं हैं। वे ऑनलाइन “मेंटॉरशिप” देते हैं, युवाओं से दोस्ती करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और फिर धीरे-धीरे उन्हें हिंसा के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि परिवार को तब तक भनक नहीं लगती, जब तक बहुत देर न हो जाए। यह भी आत्ममंथन का विषय है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था युवाओं को आलोचनात्मक सोच सिखा पा रही है? जब युवा तथ्यों की जांच करने की बजाय भावनात्मक नारों पर भरोसा करने लगते हैं, तो वे आसानी से कट्टरपंथ का शिकार बन जाते हैं। साथ ही, समाज का वह तबका जो खुद को हाशिये पर महसूस करता है, वहां कट्टर विचारधाराएं तेजी से पनपती हैं। अगर युवाओं को समान अवसर, न्याय और सुनवाई नहीं मिलती, तो वे वैकल्पिक पहचान की तलाश में खतरनाक रास्तों की ओर मुड़ सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में परिवार और समुदाय की भूमिका सबसे अहम लेकिन सबसे उपेक्षित है। माता-पिता, शिक्षक और स्थानीय नेता अगर युवाओं के व्यवहार में बदलाव, अत्यधिक गुस्सा या अलगाव को समय रहते पहचान लें, तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं।

‘विश्वास’ भारत की सबसे बड़ी मुद्रा, कुआलालंपुर में बोले पीएम मोदी— Top 3 अर्थव्यवस्था बनने के करीब भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, नए वाणिज्य दूतावास की घोषणा और तिरुवल्लुवर छात्रवृत्ति की बात कही। उन्होंने भारत को निवेश-व्यापार का वैश्विक केंद्र बताया। कार्यक्रम में 800 कलाकारों की भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत की वैश्विक प्रगति, भारत-मलेशिया संबंधों की मजबूती और भारतीय प्रवासी समुदाय की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत जल्द ही मलेशिया में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, शिक्षा और जनसंपर्क को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। इस घोषणा का भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले दस वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व और व्यापक परिवर्तन देखे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि एक दशक पहले भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज देश तेजी से प्रगति करते हुए दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के बेहद करीब पहुंच चुका है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय देश की नीतिगत सुधारों, स्थिर शासन, मजबूत लोकतंत्र और जनता के विश्वास को दिया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज ‘विश्वास’ भारत की सबसे बड़ी मुद्रा बन चुका है, जिसने दुनिया भर में भारत की साख को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत अब केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि वह निवेश और व्यापार का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बन चुका है। उन्होंने बताया कि आज दुनिया के कई प्रमुख देश भारत को विकास के लिए एक भरोसेमंद और

दीर्घकालिक साझेदार के रूप में देख रहे हैं। चाहे वह ब्रिटेन हो, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, ओमान हो, यूरोपीय संघ हो या अमेरिका—इन सभी देशों के साथ भारत के मजबूत व्यापारिक समझौते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक समुदाय भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत स्थिरता पर भरोसा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि भारत शीघ्र ही छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए तिरुवल्लुवर छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल शैक्षणिक सहयोग को बढ़ाएगी, बल्कि दोनों देशों के युवाओं के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को भी और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा, नवाचार और युवा शक्ति भारत के भविष्य के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने मलेशिया में बसे भारतीयों की विशेष सराहना की। उन्होंने कहा कि मलेशिया में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय मूल का समुदाय निवास करता है और यह समुदाय भारत और मलेशिया के बीच एक जीवंत सेतु की तरह कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय और मलेशियाई दिलों को जोड़ने वाली कई सांस्कृतिक और सामाजिक कड़ियां हैं। आपने रोटी कनाई को मालाबार परोटा से जोड़ दिया है, नारियल और मसालों की खुशबू दोनों देशों की रसोई में समान रूप से महसूस होती है, और हां, ‘तेह तारिक’ भी हमारी साझा संस्कृति का प्रतीक

बन चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे कुआलालंपुर हो या कोच्चि, इन स्वादों और परंपराओं में एक परिचित अपनापन महसूस होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय और मलेशियाई समाज एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसका एक बड़ा कारण भाषाओं में मौजूद समान शब्द और सांस्कृतिक साम्य है। उन्होंने यह उल्लेख किया कि मलेशिया में भारतीय संगीत और फिल्मों काफी लोकप्रिय हैं, जो दोनों देशों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत करती हैं। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन भारत में कई लोगों को यह बात पहले पता नहीं थी। उनकी पिछली भारत यात्रा के दौरान जब उन्होंने एक पुराना हिंदी गीत गाया, तो उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और भारतीय जनता को सुखद आश्चर्य हुआ। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह जानकर खुशी होती है कि प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को महान अभिनेता और नेता एमजीआर के तमिल गीत भी पसंद हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत की गई ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रस्तुति की भी भूरी-भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अभी-अभी हमने एक अद्भुत और अविस्मरणीय सांस्कृतिक प्रदर्शन देखा है, जिसमें 800 से अधिक नर्तकों ने पूर्ण सामंजस्य और अनुशासन के साथ नृत्य प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रस्तुति आने वाले कई वर्षों तक लोगों की स्मृति में बनी



सकता है कि उनकी जीत अपेक्षाकृत आरामदायक होगी। हालांकि, आधिकारिक परिणाम 11 फरवरी को घोषित किए जाएंगे, लेकिन आंकड़े और रुझान उनके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो, शिवसेना ने कुल 65 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को मात्र 24 सीटें ही मिलीं। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) को केवल छह सीटें मिलीं और एनसीपी (शरद पवार गुट) को सिर्फ एक सीट पर संतोष करना पड़ा। यह आंकड़ा महायुति गठबंधन की मजबूती और विपक्ष की कमजोर स्थिति को दर्शाता है। गठबंधन की रणनीति की बात करें तो शिवसेना और एमएनएस ने चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस और एनसीपी ने अकेले चुनाव लड़ने का विकल्प चुना। इससे उनके वोट बंट गए और गठबंधन को लाभ हुआ। महायुति गठबंधन की जीत इस बात का प्रमाण है कि रणनीतिक साझेदारी और सही उम्मीदवार चयन चुनाव में सफलता की कुंजी हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि रितु तावडे और संजय शंकर घाड़ी दोनों ही अपने-अपने पदों पर जीत हासिल कर महापालिका में महायुति गठबंधन का दबदबा और मजबूत करेंगे। इससे नगर निगम में गठबंधन की नीति और निर्णय प्रक्रिया पर उनका प्रभुत्व बढ़ेगा। इस प्रकार, बीएमसी चुनावों में महायुति गठबंधन का शानदार प्रदर्शन और विपक्ष के कमजोर परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है कि मुंबई नगर निगम में आगामी वर्षों में गठबंधन की सत्ता और प्रभाव अधिक मजबूत होगा।

मुंबई महापालिका में BJP का दबदबा, रितु तावडे नई मेयर, डिप्टी मेयर शिंदे गुट से

मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों में महायुति गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के बाद भाजपा नेता रितु तावडे ने महापौर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। रितु तावडे घाटकोपर के वार्ड 132 से पार्षद हैं और इस सीट से दूसरी बार चुनी गई हैं। उनके महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल करने को राजनीतिक गलियारों में महायुति गठबंधन की मजबूती और चुनावी रणनीति के एक अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है। उप महापौर पद के लिए शिवसेना (शिंदे गुट) की नेता संजय शंकर घाड़ी को गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने भी अपने नामांकन पत्र जमा कर दिए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि महायुति गठबंधन ने महापौर और उप महापौर दोनों पदों के लिए अपनी रणनीति पहले से सुनिश्चित कर रखी है। दोनों उम्मीदवारों के चुनावी अनुभव और स्थानीय लोकप्रियता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उनकी जीत अपेक्षाकृत आरामदायक होगी। हालांकि, आधिकारिक परिणाम 11 फरवरी को घोषित किए जाएंगे, लेकिन आंकड़े और रुझान उनके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो, शिवसेना ने कुल 65 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को मात्र 24 सीटें ही मिलीं। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) को केवल छह सीटें मिलीं और एनसीपी (शरद पवार गुट) को सिर्फ एक सीट पर संतोष करना पड़ा। यह आंकड़ा महायुति गठबंधन की मजबूती और विपक्ष की कमजोर स्थिति को दर्शाता है। गठबंधन की रणनीति की बात करें तो शिवसेना और एमएनएस ने चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस और एनसीपी ने अकेले चुनाव लड़ने का विकल्प चुना। इससे उनके वोट बंट गए और गठबंधन को लाभ हुआ। महायुति गठबंधन की जीत इस बात का प्रमाण है कि रणनीतिक साझेदारी और सही उम्मीदवार चयन चुनाव में सफलता की कुंजी हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि रितु तावडे और संजय शंकर घाड़ी दोनों ही अपने-अपने पदों पर जीत हासिल कर महापालिका में महायुति गठबंधन का दबदबा और मजबूत करेंगे। इससे नगर निगम में गठबंधन की नीति और निर्णय प्रक्रिया पर उनका प्रभुत्व बढ़ेगा। इस प्रकार, बीएमसी चुनावों में महायुति गठबंधन का शानदार प्रदर्शन और विपक्ष के कमजोर परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है कि मुंबई नगर निगम में आगामी वर्षों में गठबंधन की सत्ता और प्रभाव अधिक मजबूत होगा।

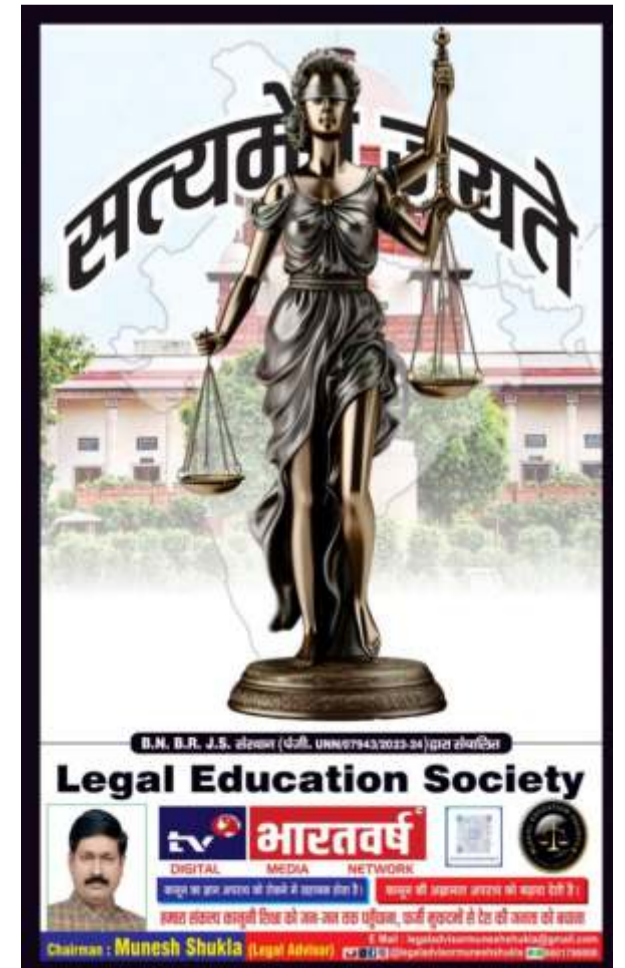
कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने दिया आश्वासन India-US समझौते से किसानों को कोई नुकसान नहीं

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को आश्वासन दिया कि सरकार ने अमेरिका-भारत व्यापार समझौते के अंतरिम ढांचे में किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सभी प्रमुख फसलों और दुग्ध उत्पादों की रक्षा की है। शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस समझौते से भारतीय निर्यात के लिए अमेरिकी बाजार खुलेंगे और उन्होंने कहा कि हमारे बासमती चावल अमेरिका में धूम मचा देंगे। कृषि मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि इससे बहुत लाभ होगा। यह भारत के किसानों और जनता के हित में है। हमने सभी प्रमुख फसलों और दुग्ध उत्पादों की रक्षा की है। दूसरी ओर, किसानों को निर्यात के लिए बाजार मिलेंगे। हमारे बासमती चावल अमेरिका में धूम मचा देंगे। हमारे मसाले वहां जाएंगे। यह किसानों के हित में है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में किसानों से बातचीत के दौरान ये टिप्पणियां कीं। भारत और अमेरिका ने पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की। संयुक्त बयान में कहा गया है कि यह रूपरेखा 13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई



व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) वार्ता के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है, जिसमें अतिरिक्त बाजार पहुंच प्रतिबद्धताएं और अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए समर्थन शामिल होगा। बयान के अनुसार, भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और खाद्य एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क समाप्त या कम करेगा, जिसमें सूखे अनाज (डीडीजी), पशु आहार के लिए लाल ज्वार, मेवे,

ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट और अन्य उत्पाद शामिल हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि घरेलू किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में दुग्ध उत्पादों, फलों, सब्जियों, मसालों और अन्य अनाजों को संरक्षित किया गया है।



Legal Education Society
DIGITAL MEDIA NETWORK
Chairman : Munesht Shukla (Legal Advisor)

रिजर्व बैंक में लीगल ऑफिसर, मैनेजर सहित कई पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू

अगर आप सरकारी बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2026 के लिए भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत आरबीआई में कई महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पदों को भरा जाएगा। इनमें लीगल ऑफिसर ग्रेड-B, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर जैसे प्रमुख पद शामिल हैं। यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास मानी जा रही है, जो बैंकिंग सेक्टर में एक स्थिर, सम्मानजनक और सुरक्षित करियर बनाना चाहते हैं। आरबीआई द्वारा जारी सूचना के अनुसार, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन कल से शुरू हो चुके हैं और इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, ताकि उम्मीदवारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 21 पदों पर नियुक्तियों की जाएंगी। इन पदों में अलग-अलग विभागों के अंतर्गत विभिन्न जिम्मेदारियों से जुड़े पद शामिल हैं, जिससे उम्मीदवारों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार अवसर मिल सके। यह भर्ती खास तौर पर उन युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है, जो बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे हैं और देश की सबसे प्रतिष्ठित वित्तीय संस्था में काम करने की इच्छा रखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक न केवल देश की मौद्रिक नीति को संचालित करता है, बल्कि कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण, आकर्षक वेतन और अनेक सुविधाएं भी प्रदान करता है। इसी कारण आरबीआई में नौकरी करना लाखों युवाओं का सपना होता है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। हालांकि, कुछ पदों के लिए सामान्य स्नातक डिग्री के अलावा विशेष विषय से संबंधित शैक्षणिक योग्यता या कार्य अनुभव की भी आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, लीगल ऑफिसर पद के लिए कानून से संबंधित डिग्री और अनुभव जरूरी हो सकता है। इसलिए सभी उम्मीदवारों



को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आरबीआई द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, ताकि पात्रता से जुड़ी किसी भी शर्त को लेकर भ्रम न रहे और आवेदन करते समय कोई गलती न हो। उम्र सीमा की बात करें तो इस भर्ती में अलग-अलग पदों के अनुसार उम्मीदवारों की आयु तय की गई है। न्यूनतम आयु सीमा कुछ पदों के लिए 21 वर्ष रखी गई है, जबकि कुछ पदों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं अधिकतम आयु सीमा पद के अनुसार 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष तक रखी गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और दिव्यांग उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट भी प्रदान की जाएगी। इससे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में समान अवसर मिल सकेगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो आरबीआई ने अलग-अलग श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए अलग शुल्क निर्धारित किया है। अनुसूचित

जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन के लिए केवल 100 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं सामान्य वर्ग और अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 600 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किया जाएगा, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे विकल्प उपलब्ध होंगे। वेतन और सुविधाओं के मामले में भी आरबीआई की यह भर्ती काफी आकर्षक मानी जा रही है। ग्रेड-B स्तर के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती वेतन लगभग 55,000 रुपये प्रति माह के आसपास मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, मेडिकल सुविधा, यात्रा भत्ता और अन्य कई सरकारी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। समय के साथ-साथ अनुभव और पदोन्नति के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी भी होती रहती है, जिससे आरबीआई में करियर लंबे समय तक सुरक्षित और लाभदायक रहता है। आवेदन करने की प्रक्रिया भी काफी सरल रखी गई है। इच्छुक

उम्मीदवार सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in पर जाएं। वेबसाइट के होमपेज पर जाकर 'Recruitment' या 'Careers' सेक्शन में प्रवेश करें। वहां "RBI Recruitment 2026" से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और अन्य आवश्यक जानकारियां सही-सही भरनी होंगी। इसके साथ ही जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट या पीडीएफ कॉपी जरूर सुरक्षित रख लें, ताकि भविष्य में किसी भी चरण पर उसका उपयोग किया जा सके। कुल मिलाकर, आरबीआई की यह भर्ती उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है, जो सरकारी बैंक में नौकरी पाना चाहते हैं और देश की शीर्ष वित्तीय संस्था का हिस्सा बनकर अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं।

सूर्यवंशी ने भोजपुरी गाने पर डांस किया, अवॉर्ड सपोर्ट स्टाफ को डेडिकेट किया



टीम के सेलिब्रेशन के एक वीडियो क्लिप में वैभव कहते हैं कि पंजाबी गाना समझ नहीं आ रहा गाइज, अब भोजपुरी लगेगा। इसके बाद वैभव ने पवन सिंह का गाना सॉरी-सॉरी प्ले किया। इसके बाद सभी खिलाड़ी इस भोजपुरी गाने पर डांस करने लगे। वीडियो के आखिरी में वैभव कहते हैं कि अब मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही काफी है। IPL की राजस्थान रॉयल्स ने डांस की वीडियो क्लिप पर कमेंट भी किया और लिखा कि 'एक बिहारी सब पर भारी'। अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में वैभव सूर्यवंशी जीत के हीरो रहे। फाइनल में 175 रन की पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा छक्के लगाने के चलते वे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। उन्होंने 7 मुकामलों में 62.71 की औसत से 439 रन बनाए, जिनमें 41 चौके और 30 छक्के शामिल थे। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने के बाद वैभव ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा। मैं ये अवॉर्ड पूरे सपोर्ट स्टाफ को डेडिकेट करना चाहता हूँ। वैभव सूर्यवंशी के दादा उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि यह उनके परिवार के लिए बेहद खुशी का पल है। उन्होंने बताया कि वैभव ने शानदार बल्लेबाजी की।

टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन हैट्रिक, रोमारियो शेफर्ड ने बनाया इतिहास

2026 टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 35 रनों से हरा दिया है। वर्ल्ड कप के पहले ही दिन हैट्रिक देखने को मिली। रोमारियो शेफर्ड वेस्टइंडीज के ऐसे पहले गेंदबाज बने हैं, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बनाए थे। इसके जवाब में स्कॉटलैंड की टीम 147 रन ही बना सकी। एक बार के लिए स्कॉटलैंड भी जीत की ओर अग्रसर थी, लेकिन रोमारियो शेफर्ड की हैट्रिक ने सारा मैच ही पलट कर रख दिया। उन्होंने 17वें ओवर में लगातार तीन गेंदों पर 3 विकेट लिए। 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्कॉटलैंड की टीम एक समय 3 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना चुकी थी और टीम का रन रेट लगभग 9 का चल रहा था। मगर इसके बाद स्कॉटलैंड की टीम लगातार विकेट खोने लगी। 17वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी करने थे। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर मैथ्यू



क्रॉस (11), तीसरी गेंद पर माइकल लीस्क (0) और चौथी गेंद पर ओलिवर डेविडसन (0) को आउट कर हैट्रिक पूरी की। वो टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के 9वें और वेस्टइंडीज के सबसे पहले गेंदबाज हैं। वेस्टइंडीज के लिए रोमारियो शेफर्ड ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए, दूसरे छोर पर जेसन होल्डर ने भी घातक गेंदबाजी करते हुए 3 बल्लेबाजों को आउट किया। उनके अलावा शमार जोसेफ और गुडाकेश मोती ने भी एक-एक विकेट चटकवाया।



इयान बिशप ने कहा, भारत वर्ल्डकप का प्रबल दावेदार

टी-20 वर्ल्डकप के पहले मैच में हारते-हारते जीता पाकिस्तान

2009 का चैंपियन पाकिस्तान टी-20 मैच में पाकिस्तान की के ओपनर वर्ल्ड कप के पहले मैच में नीदरलैंड से हारते-हारते जीत गया। टीम को जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में 29 रन बनाने थे। उसे फहीम अशरफ ने 19वें ओवर में 3 छक्के लगाकर 3 विकेट की जीत दिलाई। 18वें ओवर तक नीदरलैंड का पलड़ा भारी था। 19वें ओवर की पहली बॉल पर फहीम ने छक्का लगाया, लेकिन दूसरी बॉल पर मैक्स ओडाउड से उनका कैच ड्रॉप हो गया। जीवनदान मिलने के बाद फहीम ने दो छक्के लगाकर मैच का रुख पाकिस्तान की ओर कर दिया। उन्होंने 11 बॉल पर नाबाद 29 रन की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कोलंबो में शनिवार को खेले गए साहिबजादा फरहान ने 47 रन बनाए। वे 3 रन से फिफ्टी चूक गए। सईम अयूब ने 24 रन बनाए। नीदरलैंड की ओर पॉल वैन मीकेरेन और आर्यन दत्त को 2-2 विकेट मिले। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पहले बैटिंग कर रही नीदरलैंड की पूरी टीम 19.5 ओवर में 147 रन पर सिमट गई। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से सलमान मिर्जा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। नीदरलैंड के 10 में से 9 बल्लेबाज कैच आउट हुए, जबकि केवल एक विकेट अबरार अहमद ने कॉलिन एकरमैन को बोलड कर हासिल किया।

सिराज के लिए अच्छा मौका IND vs USA: 24 घंटे में बदली मोहम्मद सिराज की किस्मत,

सिराज टी20 विश्व कप के लिए घोषित हुई 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा नहीं थे। सिराज 2024 विश्व विजेता टीम के सदस्य थे, लेकिन उन्हें इस बार जगह नहीं मिली थी। हालांकि, हर्षित के चोटिल होने के बाहर होने की वजह से सिराज अंतिम समय में 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा बने। लग रहा था कि सिराज भले ही टीम में आने में सफल रहे हैं, लेकिन उन्हें एकादश में शामिल होने का मौका शायद ही मिले। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। 24 घंटे पहले तक टीम में नहीं रहे सिराज को पहले ही मैच में प्लेइंग-11 में शामिल किया गया इसका कारण बुमराह का बीमार होना रहा। अमेरिका ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। टॉस के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम पहले बल्लेबाजी करने को लेकर चिंता में नहीं है। सूर्यकुमार ने साथ ही बताया कि इस मैच के लिए संजू



सैमसन और वॉशिंगटन सुंदर प्लेइंग-11 हिस्सा नहीं है। वहीं, बीमार होने के कारण तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। बुमराह की जगह सिराज को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच टी20 विश्व कप में ग्रुप ए का मैच खेला जा रहा है। भारत इस टूर्नामेंट में अपने

खिताब का बचाव करने उतरा है। भारत ने इस मैच के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को जगह दी है जो 24 घंटे पहले तक टी20 विश्व कप टीम का हिस्सा भी नहीं थे। सिराज को हर्षित राणा की जगह टीम में शामिल किया गया था जो चोट के कारण अंतिम समय में इस वैश्विक टूर्नामेंट में खेलने से चूक गए।

एसबीआई का शानदार प्रदर्शन — मुनाफा 13% बढ़कर ₹21,317 करोड़ पहुंचा

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने चालू वित्त वर्ष की तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं। बैंक का शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) सालाना आधार पर लगभग 13% बढ़कर 21,317 करोड़ तक पहुंच गया है। बेहतर ब्याज आय, कर्ज वितरण में बढ़ोतरी और एनपीए (खराब कर्ज) में कमी को इस वृद्धि की प्रमुख वजह माना जा रहा है। बैंक के मुताबिक लोन ग्रोथ में लगातार सुधार देखने को मिला है, खासकर रिटेल, होम लोन और एमएसएमई सेक्टर में कर्ज की मांग बढ़ी है। इसके साथ ही जमा (डिपॉजिट) में भी इजाफा हुआ है, जिससे बैंक की कुल आय पर सकारात्मक असर पड़ा। नेट इंटरैस्ट इनकम (NII) यानी ब्याज से होने वाली कमाई भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है, जो बैंकिंग कारोबार की मजबूती को दर्शाती है। एसबीआई ने अपनी एसेट क्वालिटी में भी सुधार दर्ज किया है। बैंक का सकल एनपीए अनुपात घटा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि खराब कर्ज का दबाव कम हो रहा है। प्रावधान में कमी आने से बैंक की लाभप्रदता और बेहतर हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मजबूत बैलेंस शीट और बेहतर रिक्वैरी मैनेज्म के कारण एसबीआई लगातार बेहतर वित्तीय प्रदर्शन कर पा रहा है। बैंक प्रबंधन ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और नई तकनीक के इस्तेमाल से ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। योनो (YONO) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बड़ी संख्या में नए ग्राहक जुड़े हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी तेजी आई है। इससे परिचालन लागत कम करने में मदद मिली है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि यही रुझान जारी रहा तो आने वाली तिमाहियों में भी बैंक का प्रदर्शन मजबूत रह सकता है।



Shahid Kapoor की Farzi 2 सीक्वल के लिए मिली 45 करोड़ की फीस



पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, शाहिद को दूसरे सीज़न में अपने काम के लिए कथित तौर पर 45 करोड़ रुपये का भारी-भरकम पेमेंट मिलेगा, जो एक एक्टर के तौर पर उन्हें अब तक का सबसे ज्यादा पेमेंट है। जबकि यह बताया गया है कि शाहिद आमतौर पर प्रति फिल्म 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपये लेते हैं, वह वेब शो के लिए एक खास पेमेंट फॉर्मेट पर बातचीत करते हैं। इसके अलावा, राज और डीके, जो अपने अगले प्रोजेक्ट रक्त ब्रह्मांड पर काम करने में बिजी थे, उन्होंने फंडिंग की समस्याओं के कारण इसे शायद रोक दिया है, और इसलिए, फर्जी 2 उनका 'संकटमोचक' प्रोजेक्ट हो सकता है।

भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर लगाई रोक, घरेलू किसानों की सुरक्षा पर जोर

भारत सरकार ने अमेरिकी कृषि उत्पादों के आयात को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कई उत्पादों की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि यह कदम देश के किसानों के हितों की रक्षा और स्थानीय कृषि बाजार को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। इस निर्णय के बाद व्यापारिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और इसे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार भारत लंबे समय से कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। अधिकारियों का मानना है कि सस्ते आयातित कृषि उत्पादों के कारण स्थानीय किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता, जिससे उनकी आय प्रभावित होती है। ऐसे में सरकार ने कुछ कृषि वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध और कड़े गुणवत्ता मानकों को लागू करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता जांच को भी इस फैसले की बड़ी वजह माना जा रहा है। सरकार ने साफ किया है कि केवल वही उत्पाद देश में प्रवेश कर सकेंगे जो भारतीय मानकों और स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम किसानों को राहत देने के साथ-साथ घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखने में भी मदद कर सकता है। हालांकि, व्यापार विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले से भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर असर पड़ सकता है। अमेरिका लंबे समय से अपने कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में अधिक पहुंच की मांग करता रहा है, जबकि भारत अपने किसानों के हितों को प्राथमिकता देने की बात कहता रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत तेज होने की संभावना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों की आय बढ़ाने, एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगे भी नीतिगत कदम जारी रहेंगे। फिलहाल इस फैसले को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

क्या सिनेमाघरों में लौटेगी 'सैयारा'? टी-रिलीज को लेकर सामने आया अपडेट

फिल्म 'सैयारा' पिछले साल रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी और खूब चर्चा में रही थी। यह एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म थी, जिसमें अहान पांडे और अनीत पड्डा लीड रोल में नजर आए थे। अब यह फिल्म एक बार फिर सिनेमाघरों में टी-रिलीज को तैयार है। यह फिल्म वेलेंटाइन वीक में रिलीज होगी। वैसे 'सैयारा' फिल्म के मेकर्स यानी यशराज फिल्मस की तरफ से अभी तक दोबारा रिलीज को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन बुकमाय शो पर फिल्म के शो टाइम्स नजर आने लगे हैं। इससे साफ है कि 'सैयारा' वेलेंटाइन वीक में फिर से बड़े पर्दे पर टी-रिलीज होगी। यह फिल्म मुंबई, दिल्ली, बंगलूरू और पुणे के सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। पिछले साल जुलाई में रिलीज होने के बाद 'सैयारा' एक बड़ी हिट साबित हुई थी। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म ने वर्ल्डवाइड करीब 577 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

हाथ में वरमाला लिए शादी करने निकलीं राखी सावंत, दुल्हन लुक वायरल

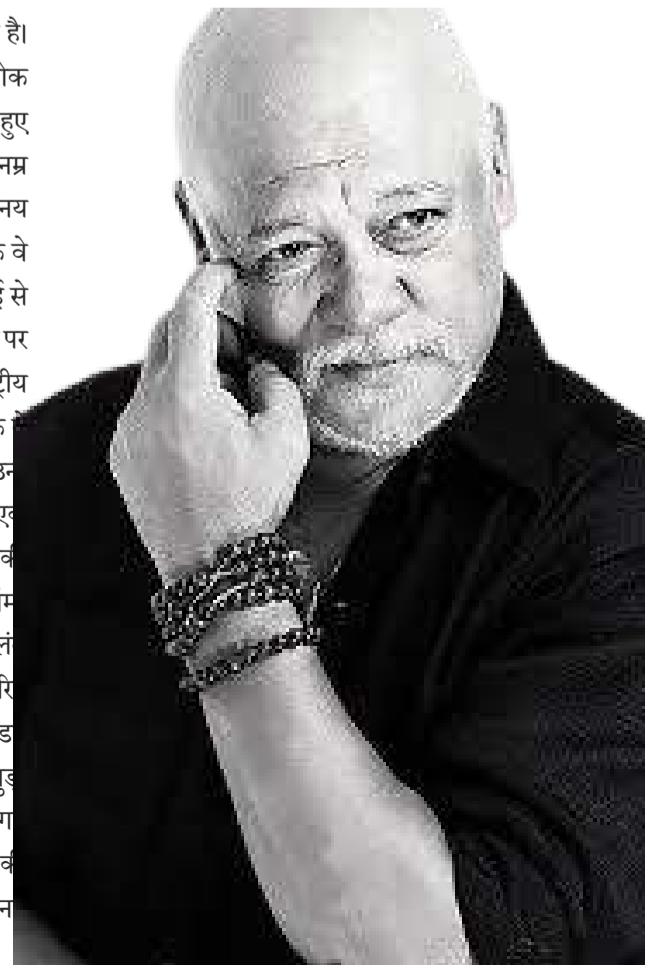
वीडियो में राखी गोलडन रंग की साड़ी पहने हुए हैं और उनका हेयरस्टाइल भी काफी अलग नजर आ रहा है। उनके बालों को लाल गुलाब से सजाया गया है, जो पूरे लुक को और खास बना रहा है। ड्रेसिंग सेंस से लेकर मेकअप तक, उनका पूरा स्टाइल फैस को काफी पसंद आ रहा है। हालांकि, फिलहाल शादी जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। राखी के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं। किसी ने लिखा, "मोहतरमा साल में कितनी बार दुल्हन बनती हैं?" तो किसी ने कहा, "ये तो एआई वाली दुल्हन लग रही है।" वहीं कुछ लोगों ने उनके लुक को डरावना भी बताया। अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें, तो राखी सावंत दो बार शादी कर चुकी हैं। साल 2019 में उन्होंने रितेश सिंह से शादी की थी, लेकिन 2022 में दोनों अलग हो गए। दोनों 'बिग बॉस 15' में भी साथ नजर आए थे। इसके बाद 2022 में उन्होंने आदिल खान दुर्गानी से शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी 2023 में टूट गया। राखी ने आदिल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था।

सिनेमा जगत को बड़ा झटका —

'मैरी कॉम' में प्रियंका चोपड़ा के कोच बने अभिनेता सुनील थापा का निधन

फिल्म इंडस्ट्री से एक दुःखद खबर सामने आई है। मशहूर अभिनेता सुनील थापा का निधन हो गया, जिससे भारतीय और नेपाली सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उन्होंने अपने लंबे करियर में कई यादगार भूमिकाएं निभाईं, लेकिन हिंदी फिल्म 'मैरी कॉम' में प्रियंका चोपड़ा के कोच की भूमिका ने उन्हें खास पहचान दिलाई थी। उनके निधन की खबर मिलते ही फिल्म जगत के कलाकारों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करना शुरू कर दिया। सुनील थापा कई दशकों से अभिनय की दुनिया में सक्रिय थे और उन्होंने नेपाली फिल्मों के साथ-साथ बॉलीवुड में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। अपने व्यक्तित्व, भारी आवाज और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस के कारण वे अक्सर सशक्त और गंभीर किरदारों के लिए जाने जाते थे। 'मैरी कॉम' फिल्म में उन्होंने बॉक्सर के मार्गदर्शक और प्रशिक्षक की भूमिका निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया था। फिल्म में उनका किरदार सख्त लेकिन प्रेरणादायक कोच का था, जिसने कहानी को भावनात्मक गहराई दी। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते उनका इलाज

परिवार की ओर से विस्तृत चिकित्सकीय जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। उनके निधन की पुष्टि होते ही नेपाल और भारत दोनों जगह उनके प्रशंसकों में शोक का माहौल बन गया। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकारों ने उन्हें याद करते हुए कहा कि सुनील थापा न केवल एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे, बल्कि बेहद विनम्र और सहयोगी इंसान भी थे। सेट पर वे नए कलाकारों की मदद करते और अभिनय की बारीकियां समझाते थे। उनके साथ काम कर चुके लोगों का कहना है कि वे अपने काम के प्रति अत्यंत अनुशासित थे और हर किरदार की तैयारी गहराई से करते थे। सुनील थापा ने अपने करियर में एक्शन, ड्रामा और सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई टीवी प्रोजेक्ट्स और अंतरराष्ट्रीय प्रोडक्शंस में भी अभिनय किया था। उनके अभिनय की खासियत यह थी कि छोटे रोल में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा देते थे। यही वजह रही कि उनकी सीमाओं से परे पहचान मिली और वे भारत-नेपाल सांस्कृतिक संबंधों का भी एक अहम चेहरा बन गए। उनके निधन के बाद प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उन फिल्मों के दृश्य साझा करते हुए श्रद्धांजलि दी। कई लोगों ने लिखा कि 'मैरी कॉम' में उनका किरदार आज भी प्रेरणा देता है और उनकी आवाज व अभिनय लंबे समय तक याद किए जाएंगे। फिल्म समीक्षकों का मानना है कि उन्होंने चरित्र अभिनेता की श्रेणी में एक अलग पहचान बनाई, जहां अभिनय का प्रभाव स्टारडम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। परिवार की ओर से अंतिम संस्कार से जुड़े जानकारी बाद में साझा किए जाने की बात कही गई है। उनके जाने से फिल्म जगत ने एक अनुभवी कलाकार खो दिया है, जिसकी कमी लंबे समय तक महसूस की जाएगी। सुनील थापा अपने पीछे फिल्मों की समृद्ध विरासत और अनगिनत यादगार किरदार छोड़ गए हैं, जो दर्शकों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे।



बिना कनेक्शन भेज दिए हजारों के वॉटर बिल, जलकल विभाग पर लापरवाही का आरोप, महिलाओं का प्रदर्शन



LPL ऑक्शन के खिलाफ क्रिकेट खिलाड़ियों का प्रदर्शन

लखनऊ में 7 मार्च से होने वाले लखनऊ प्रीमियर लीग (LPL) के ऑक्शन के बाद लोकल खिलाड़ी विरोध में उतर आए हैं। क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन से जुड़े खिलाड़ियों ने LPL और लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ शनिवार को प्रदर्शन किया। वे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लखनऊ (CAL) के कार्यालय पर पहुंच गए। प्लेयर्स के CAL पहुंचने पर बीबीडी बैडमिंटन एकेडमी का गेट बंद कर दिया गया। खिलाड़ियों ने लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन के हेड नवनीत सहगल और खलीक अहमद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। उनका कहना है कि LPL में दूसरे जिलों के खिलाड़ियों को मौका दिया गया। LPL लखनऊ के खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला जो कि योग्य और मेहनती हैं। खिलाड़ियों को मनाने के लिए लीग के कमिश्नर एसपी मिश्र पहुंचे। उन्होंने बात करने की कोशिश की। इसी दौरान खिलाड़ियों से उनकी कहासुनी शुरू हो गई। इसके बाद कमिश्नर को वहां से जाना पड़ा। इस दौरान उनके पीछे खिलाड़ियों ने मुर्दाबाद के नारे लगाकर सड़क तक भेज दिया। खिलाड़ियों के साथ उनके घरवाले भी प्रदर्शन में पहुंचे। इसके साथ ही दो ग्रुप और हैं। एक टीम को स्क्वाड में 15 खिलाड़ी रखना होगा। ऑक्शन में खिलाड़ियों की न्यूनतम 5 हजार रुपए से लेकर 1.25 लाख तक की अधिकतम बोली लगेगी। बोली बराबर होने पर नहील चलाकर टीम का चयन किया जाएगा। लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुजय त्रिपाठी ने बताया- IPL और यूपी टी-20 में यूपी से खेलने वाले 6 खिलाड़ी बतौर मार्केट प्लेयर लीग में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें जीशान अंसारी, नमन तिवारी, अंश यादव, विप्रज निगम, उषेंद्र यादव, कृतज्ञ कुमार सिंह शामिल हैं। इनकी कीमत डेढ़ लाख रुपए है। ये बतौर स्टार प्लेयर टीमों में शामिल होंगे।



है। कॉलोनी निवासी रश्मि ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि उनके घर में आज तक कभी पानी का कनेक्शन नहीं लगाया गया। इसके बावजूद जलकल विभाग की ओर से उन्हें 16 हजार रुपये का पानी बिल भेज दिया गया है। रश्मि का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह कॉलोनी की रहने वाली अंजलि ने बताया कि उनके नाम 22 हजार 400 रुपये का बकाया दिखाया गया है, जबकि उनके घर में जलकल विभाग की कोई सप्लाई नहीं है और वे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हैंडपंप या अन्य साधनों पर निर्भर हैं। इस मामले में 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला विश्वा की स्थिति और भी चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और वे दूसरों की मदद से किसी तरह जीवन यापन कर रही हैं। इसके बावजूद जलकल विभाग ने उनके नाम 20 हजार 500 रुपये का पानी बिल भेज दिया है। बुजुर्ग महिला का कहना है कि

इतनी बड़ी रकम चुकाना उनके लिए नामुमकिन है और यह उनके साथ सीधा अन्याय है। कॉलोनीवासियों का आरोप है कि बिना पानी कनेक्शन के बिल भेजना जलकल विभाग की घोर लापरवाही और आम लोगों का उत्पीड़न है। लोगों का कहना है कि विभाग ने न तो कभी कनेक्शन दिया और न ही पानी की सप्लाई की, फिर भी बिल भेजकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि या तो रिकॉर्ड में गंभीर गड़बड़ी है या फिर जानबूझकर गरीब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इस लापरवाही के खिलाफ शुरूवार को लेबर कॉलोनी की महिलाएं एकजुट होकर नगर निगम मुख्यालय पहुंचीं और जलकल विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि वे सुबह से ही नगर निगम कार्यालय में मौजूद रहीं, लेकिन उनकी शिकायत सुनने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी सामने नहीं आया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की

बेखुबी और उदासीन रवैया उनकी परेशानी को और बढ़ा रहा है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि बिना कनेक्शन के भेजे गए वॉटर बिलों को माफ नहीं किया गया, तो वे मजबूरन बड़े स्तर पर धरना-प्रदर्शन करेंगी। महिलाओं ने कहा कि वे शनिवार को एक बार फिर नगर निगम पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराएंगी। उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक वे चुप नहीं बैठेंगी। कॉलोनीवासियों की मांग है कि जलकल विभाग द्वारा बिना पानी कनेक्शन के भेजे गए सभी वॉटर बिलों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। कॉलोनीवासियों ने प्रशासन से अपील की है कि उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तत्काल राहत दी जाए और उन्हें मानसिक तनाव से मुक्त किया जाए। अब देखना यह होगा कि नगर निगम और जलकल विभाग इस मामले में कितनी जल्दी और क्या कार्रवाई करते हैं।

लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित दरियापुर लेबर कॉलोनी में बिना पानी कनेक्शन के ही हजारों रुपये के वॉटर बिल भेजे गए। इससे परेशान महिलाओं ने नगर निगम में प्रदर्शन किया। कॉलोनीवासियों ने बिल रद्द करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की, अन्यथा आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।

राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम क्षेत्र स्थित दरियापुर की लेबर कॉलोनी में जलकल विभाग की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बिना किसी पानी कनेक्शन के ही हजारों रुपये के वॉटर बिल भेज दिए गए हैं। इन बिलों की राशि 16 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक बताई जा रही है। अचानक इतने बड़े बिल मिलने के बाद कॉलोनीवासी, खासकर महिलाएं, बेहद परेशान और चिंतित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके घरों में कभी भी जलकल विभाग का पानी कनेक्शन नहीं लगाया गया, इसके बावजूद विभाग की ओर से उन्हें भारी-भरकम बिल थमा दिए गए हैं। लेबर कॉलोनी में रहने वाले अधिकतर परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। यहां की अधिकांश महिलाएं घरों में झाड़ू-पोछा, बर्तन और अन्य घरेलू काम करके किसी तरह अपने परिवार का खर्च चलाती हैं। ऐसे में हजारों रुपये का पानी बिल चुकाना उनके लिए असंभव है। महिलाओं का कहना है कि रोज की जरूरतें पूरी करना ही उनके लिए मुश्किल होता है, ऐसे में अचानक आए इन बिलों ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी

लखनऊ में सुभासपा विधायक के खिलाफ लेखपाल और पार्षद करेंगे शिकायत

लखनऊ में सुभासपा विधायक बेदीराम का एक वीडियो सामने आया। इसमें नाले की जमीन से कब्जा हटाने पहुंचे नगर निगम के लेखपाल को डांटने और अभद्रता का आरोप है। इसी को लेकर 7 फरवरी को लेखपाल कौशल, मेयर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग करेंगे। साथ ही पुलिस से शिकायत कर मुकदमा दर्ज कराने की योजना है। स्थानीय पार्षद ममता रावत का भी कहना है कि अभद्र भाषा का मेरे लिए प्रयोग किया गया। अब मेयर से मिलने के बाद आगे क्या करना है, इसका एजेंडा तैयार करूंगा। वहीं, विधायक बेदीराम ने गाली देने के आरोप को गलत बताते हुए कहा कि सामने आए संबंधित वीडियो में मेरी आवाज नहीं है। नगर निगम नाले के लिए जो नियम के अनुरूप है वहीं जमीन लेगा, न कि किसी की निजी संपत्ति। आरोप है इस वीडियो में विधायक फोन पर लेखपाल को डांट-फटकार रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वहां जाने की। नौकरी करना मुश्किल कर दूंगा। इस पर जब लेखपाल स्थानीय महिला पार्षद के कहने पर कार्रवाई की बात कहता है तो विधायक महिला पार्षद को भी गालियां देते हैं। लेखपाल कौशल ने कहा- पुलिस से शिकायत कर मुकदमा दर्ज कराएंगे। वहीं, विधायक ने सभी आरोपों को नकारा है। उनका कहना

है कि हमने अपने बच्चों से बात की थी। नगर आयुक्त ने कार्रवाई रुकवाई थी, हमने नहीं। दरअसल, गोपती नगर के भरवारा के गंगोत्री विहार फेज-टू में नाले पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। यहां विधायक का मैरिज हाल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विधायक ने नाले की जमीन पर कब्जा कर रखा है। नगर निगम की टीम शुरूवार को बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची थी। कार्रवाई शुरू करते इससे पहले विधायक के बेटे और भतीजे भी पहुंच गए। बेटे ने तुरंत बेदीराम को फोन लगा दिया और लेखपाल को पकड़ा दिया। आरोप है कि लेखपाल कौशल के साथ विधायक ने अभद्रता की। इसके बाद नगर निगम टीम मौके से वापस लौट आई। लेखपाल ने मामले की जानकारी नगर आयुक्त और अधिकारियों को दी है। उन्होंने कहा- अगर कार्रवाई नहीं होगी तो नौकरी छोड़ दूंगा। स्थानीय पार्षद ममता रावत ने कहा- मेयर को जानकारी देंगे। नाले की जमीन पर कब्जा करने के कारण पीछे कॉलोनी में जलभराव हो रहा है। इससे लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम की टीम बिना उन्हें बताए कार्रवाई करने पहुंची थी। जब शाम को नगर निगम के ऑफिस गई तब यह बात पता चली। सुषमा खर्कवाल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो किसी भी पद पर हो अगर वह सरकारी जमीन



पर कब्जा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधायक बेदीराम ने कहा- नाले के जमीन की पैमाइश होगी। जो नियम संगत है, वही होना चाहिए। उन्होंने बताया- मेरा मैरिज लॉन है। लेखपाल बार बार पैसा लेकर वहां पर आ जाता है। इस मामले को लेकर सदन में भी मुद्दा उठाया था। इसमें जवाब भी मांगा गया था। मामले में मेयर और नगर आयुक्त से बात करूंगा। नगर निगम और लेखपाल शासन की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। हमने कोई गाली नहीं दी है। अपने बच्चों से बात की है। आरोप पूरी तरह निराधार हैं। काम हमने नहीं नगर आयुक्त ने फोन कर रुकवाया था। वीडियो में मेरी आवाज नहीं है।

भारत में जाति नहीं, वर्ण व्यवस्था थी: राज्यपाल

लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में, गुरुवार को भारतीय ज्ञान परंपरा (IKS) पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बतौर मुख्य अतिथि सेमिनार का उद्घाटन किया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि भारतीय शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था थी। क्या किसका गुण है, उसके आधार पर वर्ण बनाया, क्या किसका कर्म है, उसके आधार पर ही परिभाषा दी गई। जाति तब थी ही नहीं। पर यदि आज एक बिंदु SC कहता है कि आज हम पुनः जाति परंपरा की ओर जाना चाहते हैं, तो मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जाति व्यवस्था कहीं भी भारत में नहीं थी। मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं कि वोट की राजनीति ने जाति परंपरा को स्थापित किया है। इस दौरान राज्यपाल ने महाभारत कालीन बर्बरिक की कहानी बताई। कहा कि जब युद्ध खत्म हुआ तो

पांडवों ने पूछा कि इस युद्ध में हमसे कौन सबसे वीर था। इसके जवाब के लिए श्रीकृष्ण सभी को बर्बरिक के पास लेकर गए। बर्बरिक का सिर पहाड़ी पर रखा हुआ था और पूरे युद्ध को उन्होंने वहीं से देखा था। जब बर्बरिक से इसका जवाब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि आप लोग तो सिर्फ हाथ-पैर चला रहे थे। इस युद्ध में लड़ने का काम तो सिर्फ श्रीकृष्ण के इशारे पर उनके सुदर्शन चक्र ने किया है। जब लोगों को युद्ध कैसे लड़ा जाता है, इसकी जानकारी नहीं थी, तब हमारे यहां महाभारत जैसे महासंग्राम हुए और सटीक टारगेट करके अस्त्र-शस्त्रों ने वार किए। आज का एटम बम भी टारगेट नहीं कर पाता है। गाजियाबाद में 3 बहनों ने सुसाइड की घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय वह था, जब भारतीय समाज में राजा जनक अपनी बेटी सीता के लिए स्वयंवर करते थे। आज ये दिन आ गए हैं। आप खुद ही दोनों सभ्यताओं की तुलना कर लीजिए। पहले जब जर्मन विद्वान मैक्सम्यूलर भारत आए तो भाषा ज्ञान न होने के कारण वह वेद को जान नहीं सके। जब वह लौटकर जर्मनी गए तो वहां अनुवाद कर वेदों को ठीक तरह से जाना और कहा कि वास्तव में वेद ही हैं जिनमें सब कुछ है। जरा सोचिए, भारत ने अगर शून्य और दशमलव न दिया होता तो आखिर कैसे गणित विषय चलता? आर्यभट्ट के शून्य के आविष्कार के बाद ही दुनिया में गणनाएं शुरू हो सकीं।



लखनऊ में UGC के समर्थन में सुहेलदेव आर्मी का हंगामा

लखनऊ में सुहेलदेव आर्मी के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी के समर्थन में विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए यूजीसी को जल्द लागू करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ते देख पुलिस प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा। सुहेलदेव आर्मी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पासी ने बताया- हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा के बाहर एकत्र हुए और यूजीसी के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना था कि यूजीसी को तुरंत लागू किया जाए ताकि उच्च शिक्षा में समानता और न्याय सुनिश्चित हो सके। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ने और प्रदर्शन के उग्र होने की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को विधानसभा की ओर बढ़ने से रोका और स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। पुलिस ने हालात बिगड़ने से पहले कार्रवाई करते हुए सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें पुलिस वैन के जरिए ईको गार्डन भेज दिया गया, जहां आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

मलिहाबाद तहसील दिवस में भड़के वकील

मलिहाबाद तहसील परिसर में शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के दूर-दराज से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी-अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर पहुंचे। तहसील दिवस का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित समाधान करना होता है, लेकिन इस दौरान प्राप्त अधिकांश शिकायतें राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग से संबंधित रहीं। लोगों ने भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, कब्जे से जुड़े मामले, स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और पुलिस से संबंधित शिकायतें अधिकारियों के समक्ष रखीं। फरियादियों की संख्या अधिक होने के कारण तहसील परिसर में दिन भर चहल-पहल बनी रही। इसी तहसील दिवस के अवसर पर मलिहाबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने एसीपी कोर्ट के संचालन को शीघ्र प्रारंभ कराने तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 76 के अंतर्गत लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण की मांग की। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले लगभग पांच वर्षों से एसीपी कोर्ट का संचालन पूरी तरह से बंद है। इसके कारण न केवल अधिवक्ताओं को बल्कि क्षेत्र के ग्रामीण निवासियों और आम जनता को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यायालय के बंद रहने से लोगों को अपने मामलों के लिए अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है। इस स्थिति को लेकर जनता में काफी रोष व्याप्त है। अधिवक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 76 की उपधारा (2) और (3)

में किए गए स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी की जा रही है। इन प्रावधानों के अनुसार, यदि पांच वर्ष की निर्धारित अवधि पूरी हो जाती है, तो असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर स्वतः संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर बन जाता है। इसके बावजूद वर्तमान में धारा 76 के अंतर्गत बड़ी संख्या में मामले अनावश्यक रूप से लंबित पड़े हुए हैं, जिससे किसानों और भूमिधरों को अपने अधिकारों के लिए भटकना पड़ रहा है। मलिहाबाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और समस्त अधिवक्ताओं की एक संयुक्त बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि प्रशासन द्वारा 48 घंटे के भीतर उनकी मांगों पर कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता है, तो 9 फरवरी 2026 को तहसील मलिहाबाद स्थित सभी राजस्व न्यायालयों का पूर्ण बहिष्कार किया

जाएगा। इसके पश्चात 10 फरवरी 2026 से सभी राजस्व न्यायालयों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त तहसील दिवस के दौरान समाज से युसुफ नामक एक व्यक्ति ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से संबंधित एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र में जर्जर सड़क के निर्माण की मांग की।



यूपी में 'घूसखोर पंडत' के खिलाफ ब्राह्मणों का अर्धनग्न प्रदर्शन

यूपी में मनोज बाजपेयी की फिल्म 'घूसखोर पंडत' के नाम को लेकर विरोध जारी है। आगरा में ब्राह्मण समाज के लोगों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और शंखनाद किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ब्राह्मणों का अपमान बंद होना चाहिए। उनकी सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को बार-बार आहत किया जाता है। भाजपा नेता अर्पणा यादव ने कहा कि इस तरह की असंवेदनशील बातें कहना या लिखना, वह भी एक ऐसे समाज के बारे में, जिसने पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति को जीवित रखा है, ठीक नहीं है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इससे पहले गुफवार को लखनऊ में सीएम के निर्देश पर फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने केंद्र से मामले में दखल देने की अपील की थी। बाद में सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म से इस टाइल को हटाने का निर्देश दिया था। विरोध के बीच डायरेक्टर नीरज पांडेय ने भी सभी प्लेटफॉर्म से फिल्म के प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला किया था। फिल्म 'घूसखोर पंडत' को नीरज पांडेय और रीतेश शाह डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में मनोज बाजपेयी, नुसरत भरूच और श्रद्धा दास प्रमुख किरदारों में नजर आ रहे हैं। इसका टीजर तीन फरवरी को रिलीज हुआ था। फिल्म इसी साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

टीजर में मनोज बाजपेयी सीनियर इंस्पेक्टर अजय दीक्षित के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिन्हें दिल्ली में 'पंडत' के नाम से जाना जाता है। फिल्म में उन्हें एक बदनाम पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाया गया है। टीजर के मुताबिक, दीक्षित 20 साल पहले सब-इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती हुए थे। अपने

कारनामों की वजह से उन्हें बार-बार डिमोट किया गया। एक बार वो घायल लड़की को बचाने के चक्कर में बुरी तरह फंस जाते हैं, जिससे उनकी जिंदगी बदल जाती है। नीरज पांडेय वही निर्देशक हैं, जिन्होंने एमएस धोनी : द अनटोल्ड स्टोरी और बेबी जैसी फिल्में बनाई हैं। कानपुर में अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा ने घूसखोर पंडत फिल्म को लेकर मार्च निकाला। इस दौरान हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। करीब 100 से अधिक सदस्य जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा। साथ ही फिल्म को नेटफ्लिक्स पर पूरी तरह से बैन करने की मांग की। हरदोई कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष सिंह ने कहा- ब्राह्मण समाज को अपमानित करने वाली घूसखोर पंडत फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के साथ कलाकारों पर एफआईआर दर्ज हो। 'घूसखोर पंडत' जैसा शीर्षक देकर जानबूझकर ब्राह्मण समाज की छवि को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। घूसखोर पंडत फिल्म के विरोध में ब्राह्मण समाज के लोगों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। शनिवार को सिकंदरा क्षेत्र परशुराम चौक पर शंखनाद किया। बोले- फिल्म पर रोक नहीं लगी तो सड़कों पर उतर उग्रप्रदर्शन किया जाएगा। ब्राह्मणों का अपमान बंद हो। सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को हर बार आहत किया जाता है। अब नहीं सहेंगे। भाजपा नेता अर्पणा यादव ने कहा- इस तरह की असंवेदनशील बात करना या लिखना, वो भी एक ऐसे समाज के बारे में, जिसने हमेशा इस पूरी दुनिया में सनातन समाज को जीवित रखा है। यह ठीक नहीं है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं, जहां बहुत



ज्यादा जातिगत टिप्पणी करना असंवैधानिक भी है। मुख्यमंत्री ने फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ जो FIR करवाने का निर्णय लिया है, मैं इसका स्वागत करती हूँ। विनय पाठक ने कहा- फिल्म में जिस तरह से एक विशिष्ट वर्ग को निशाना बनाकर नकारात्मक छवि पेश की गई है, वह सामाजिक न्याय और सम्मान की भावना के पूरी तरह खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में न केवल हमारे संस्कारों और शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, बल्कि इसका सबसे घातक प्रभाव युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों पर पड़ता है। जब मनोरंजन के नाम पर किसी समाज विशेष को गलत ढंग से पेश किया जाता है, तो इससे समाज में नफरत, अविश्वास और असमानता की स्थिति पैदा होती है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज समेत सभी वर्गों ने भारत के राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, ज्ञान और

संस्कृति में ऐतिहासिक योगदान दिया है, जिसे इस तरह के चित्रण से धूमिल करना अनुचित है। कुलपति ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन यह स्वतंत्रता सामाजिक जिम्मेदारी के बिना अधूरी है। मनोरंजन के नाम पर ऐसी सामग्री परोसना, जिससे सामाजिक तनाव या विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो, किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की पहुंच आज के युवाओं और छात्रों तक बहुत आसान है। ऐसी फिल्में उनके सोचने-समझने के नजरिए को दूषित कर सकती हैं, जिससे शैक्षणिक परिसरों के सौहार्दपूर्ण माहौल और सामाजिक रिश्तों में कड़वाहट आने की आशंका रहती है।

कानपुर में AIMIM की चुनावी सक्रियता तेज, सपा-कांग्रेस ने औवेसी टैली पर कसा तंज



कानपुर के साथ यूपी 2027 विधानसभा चुनाव में औवेसी की पार्टी AIMIM जुट गई है। आल इण्डिया मजलिस -ए- इतेहादुल मुसलमीन ने यूपी में पिछले दो महीनों में 10 लाख से अधिक सदस्यों को जोड़ने का दावा किया है। पार्टी के अनुसार अब पूरे उत्तर प्रदेश में 86 लाख से ज्यादा सदस्य रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुसलमीन लगातार यूपी में अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। पार्टी का दावा है कि बिहार और महाराष्ट्र की तरह यूपी के 2027 विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। वहीं इस पर सपा और कांग्रेस ने औवेसी पर धर्म की राजनीति करने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी ने कहा कि AIMIM की राजनीति धर्म आधारित है और ऐसा संगठन इस देश को कभी नहीं संभाल सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ही ऐसे संगठनों को तवज्जो देकर पनपने देती है। उन्होंने कहा कि अगर AIMIM के पास सच में 87 लाख सदस्य हैं, तो हिम्मत है तो यूपी में कहीं एक रैली कच्चे दिखा दें, जिसमें 2 लाख लोग इकट्ठा हो जाएं। उन्होंने सवाल किया कि यूपी में इतने जुलूम हुए, लेकिन भाषण देने के अलावा औवेसी कहीं सड़क पर नजर नहीं आए। सपा नेताओं ने कहा कि AIMIM का सदस्यता जोड़ने का दावा उनका निजी मामला है। लेकिन यूपी में अगर बीजेपी के अलावा कोई विकल्प है, तो वह सिर्फ समाजवादी पार्टी है।

उन्होंने कहा कि AIMIM को यह गलतफहमी है कि इतने सदस्य होने से वे कुछ बड़ा कर लेंगे। कानपुर के नगर उपाध्यक्ष नूर आलम ने कहा कि कांग्रेस और सपा हम पर यह आरोप लगाती हैं कि हम बीजेपी की 'बी टीम' हैं। लेकिन सपा यह बताए कि जब वह खुद धीरे-धीरे "समाजवादी पार्टी" होती जा रही है, तो उसके ही सदस्य छुपकर AIMIM की सदस्यता क्यों ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने के बजाय सपा को अपना काम गिनाना चाहिए।



उन्नाव: शिव मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा, तहसील परिषद में ग्रामीणों का हंगामा

उन्नाव में शिव मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण के विरोध में शनिवार को 50 से अधिक ग्रामीणों ने सदर तहसील परिषद में धरना-प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भूमिफिया उनकी धार्मिक आस्था से जुड़े मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने "मंदिर की जमीन पर कब्जा नहीं चलेगा" और "जय श्रीराम" के नारे लगाए। उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि वे कोतवाली सदर क्षेत्र के ग्राम लोहनहार और आसपास के गांवों के निवासी हैं। उन्होंने वर्षों पहले सामूहिक सहयोग से इस शिव मंदिर की स्थापना की थी, जिससे क्षेत्र के लोगों की गहरी धार्मिक आस्था जुड़ी है। ग्रामीणों के अनुसार, यह घटना 13 मई 2013 की है। गांव लोहनहार निवासी जसवंत और बउल्वा, जो मेवालाल के पुत्र हैं, ने कथित तौर पर मंदिर परिसर में नींव खुदवाकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी भी दी। प्रदर्शन में शामिल राम प्रसाद, लल्लू और रामऔतार सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर परिसर एक सार्वजनिक धार्मिक स्थल है। इस पर किसी भी प्रकार का निजी निर्माण पूरी तरह अवैध है। ग्रामीणों का कहना है कि इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी है, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों ने सदर तहसील प्रशासन को एक लिखित प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने मांग की कि जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में हो रहे अवैध निर्माण को तुरंत रोकना जाए और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। धरना-प्रदर्शन की सूचना मिलने पर तहसील प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



कानपुर में सपा MLA अमिताभ का बड़ा दावा

कानपुर में एसआईआर (स्पेशल इंटेसिव रिवीजन) प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेई ने इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का दावा करते हुए चौंकाते वाला खुलासा किया है। उनका आरोप है कि पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) वर्ग के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए सुनियोजित तरीके से फर्जी फॉर्म-7 भरे जा रहे हैं। विधायक ने दावा किया कि उन्होंने ऐसे हजारों फॉर्म-7 बरामद किए हैं, जिन्हें मतदाताओं की जानकारी और सहमति के बिना भरा गया है। आर्य नगर विधानसभा सीट से सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने शुक्रवार को मीडिया के सामने सैकड़ों फॉर्म-7 दिखाते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने बताया कि ये फॉर्म मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए उपयोग किए जाते हैं और इनका इस्तेमाल जानबूझकर एक खास वर्ग के वोटर्स को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने के लिए किया जा रहा है। विधायक ने वीडियो जारी कर हजारों की संख्या में फॉर्म दिखाए, जिससे पूरे मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। अमिताभ बाजपेई का आरोप है कि भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष दीपक शुक्ला ने कानपुर के नारायणी देवी धर्मशाला स्थित एक बूथ पर सैकड़ों पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम से फर्जी तरीके से फॉर्म-7 भरकर उन्हें जमा कराया। उन्होंने कहा कि इन

फॉर्मों पर जिन मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनके नाम कटवाने के लिए आवेदन किया गया है। यह सीधा-सीधा चुनावी प्रक्रिया में हेराफेरी और संविधान के खिलाफ किया गया कृत्य है। सपा विधायक ने यह भी बताया कि जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और इस संदिग्ध गतिविधि पर सवाल उठाए, तो आरोपित भाजपा नेता फॉर्म-7 के बंडल वहीं छोड़कर मौके से भाग निकले। इसके बाद इन फॉर्मों को कब्जे में लेकर पूरे मामले का खुलासा किया गया। विधायक का कहना है कि यह कोई एक-दो फॉर्म का मामला नहीं है, बल्कि हजारों की संख्या में ऐसे आवेदन भरे गए हैं, जो दर्शाता है कि यह एक सुनियोजित और संगठित प्रयास है। अमिताभ बाजपेई ने आरोप लगाया कि कानपुर में अनेक और असंवैधानिक तरीकों से पीडीए वर्ग के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि चुनावी लाभ उठाया जा सके। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इस खुलासे के सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की संभावना जताई जा रही है, जबकि राजनीतिक गलियारों में यह मुद्दा तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है।



सवर्ण संगठनों की पदयात्रा रोकी गई, धारा 144 के बीच अध्यक्ष पंकज धवरिया नजरबंद; पुलिस-प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक

हाथरस में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद और अन्य सवर्ण संगठनों द्वारा यूजीसी बिल और एससी/एसटी एक्ट के विरोध में प्रस्तावित पदयात्रा को पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। यह पदयात्रा हाथरस से दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास तक जानी थी। सुबह से ही आगरा रोड पर शहीद पार्क के आसपास का पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। पदयात्रा में शामिल होने की घोषणा करने वाले जन संगठनों के नेताओं और पदाधिकारियों को पुलिस ने नजरबंद कर लिया। राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के अध्यक्ष पंकज धवरिया को भी उनके कंचन नगर स्थित घर पर नजरबंद किया गया। आगरा रोड पर शहीद पार्क के सामने एसडीएम सदर राजबहादुर और सीओ सादाबाद अमित पाठक भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरिया के घर पर सीओ सिटी योगेंद्र कृष्ण नारायण की मौजूदगी में भी पुलिस बल तैनात था। जब अध्यक्ष ने अकेले झंडा लेकर पदयात्रा शुरू करने का प्रयास किया, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान उनकी पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। वहां पर कुछ पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई। पंकज धवरिया ने अकेले ही नारेबाजी करते हुए कहा कि यूजीसी बिल और एससी/एसटी एक्ट के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने पदयात्रा को जबरन रोका है। अधिकारियों ने बताया कि जिले में निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू है, इसलिए किसी भी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। घटना के बाद अध्यक्ष पंकज धवरिया अपने घर के बाहर अकेले धरने पर बैठ गए। पुलिस ने उनसे मिलने आए कुछ लोगों को भी वहां आने से रोका। आगरा रोड और कंचन नगर सहित आसपास का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील रहा। खुफिया तंत्र भी इस पर निगाह रखता रहा कि आखिर इस पदयात्रा और प्रदर्शन में कौन-कौन शामिल होने आ रहा है। कुछ समय बाद घर के

बाहर बैठी पंकज धवरिया साथ बरेली से इस अलंकार गंगोत्री अपनी टीम के साथ करने पर बैठकर सभी से हनुमान चालीसा पाठ कराया और उन्होंने सरकार से नीति नियम पर जमके बरसे मोदी जी को सरकार को सनातन संस्कृति स्वर्ण समाज का विरोध थी करार दिया घटना के चलते पूरे दिन क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी रही और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आसपास के जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुला लिया। प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई, वहीं आगरा रोड पर वाहनों की आवाजाही आंशिक रूप से प्रभावित रही। स्थानीय व्यापारियों ने भी स्थिति को देखते हुए कुछ समय के लिए अपनी दुकानें बंद रखीं। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और बिना अनुमति किसी भी बड़े जमावड़े या मार्च की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि पदयात्रा निकलती तो इससे जनजीवन प्रभावित होता और टकराव की आशंका भी थी, इसलिए पहले से ही रोकथाम के कदम उठाए गए। वहीं परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात दिल्ली तक पहुंचाना चाहते थे और प्रशासन ने उनकी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के अधिकार को सीमित किया है। शाम तक पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी करते रहे। देर शाम सुरक्षा व्यवस्था यथावत रखते हुए कुछ स्थानों पर बल की संख्या कम की गई, लेकिन संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनाती जारी रही। फिलहाल प्रशासन ने साफ किया है कि आगामी दिनों में भी बिना अनुमति किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर सख्ती बरती जाएगी।

मायावती ने दी चेतावनी, विधानसभा चुनाव नजदीक, पार्टी को ताकतवर बनाए रखने का संदेश

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती एक्शन मोड में हैं। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कमर कसकर मैदान में उतरने, हर विधानसभा सीट पर सक्रिय रहने, संगठन और जनाधार मजबूत करने, विपक्षी दलों की साजिशों से सतर्क रहने और धर्म-जाति राजनीति से फैल रही नफरत पर ध्यान देने का निर्देश दिया।



यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। पार्टी की तैयारी और चुनावी रणनीति को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया है। शुक्रवार को उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक की, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। इस बैठक का उद्देश्य केवल चुनावी तैयारियों की समीक्षा करना ही नहीं था, बल्कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने, जनाधार बढ़ाने और विपक्षी दलों की चालों से सतर्क रहने पर जोर देना भी था। मायावती ने बैठक के दौरान उपस्थित सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कहा कि अब समय बहुत कम बचा है, ऐसे में हर सदस्य को पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ मैदान में उतरना होगा। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि पार्टी को कमजोर करने के लिए लगातार साजिशें रची जा रही हैं, इसलिए हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी ऐसी चालों से सतर्क रहें और अपना ध्यान संगठन और जनाधार बढ़ाने

पर केंद्रित रखें। बैठक में प्रदेश मंडल अध्यक्ष, 403 विधानसभा सीटों के प्रभारी और भाईचारा समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। संगठन विस्तार, जनाधार बढ़ाने और पूरे साल की गतिविधियों की समीक्षा इस बैठक के मुख्य एजेंडे में शामिल थी। मायावती ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए हर सदस्य को एंडी-चौटी का जोर लगाना होगा। जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना और पार्टी की उपलब्धियों को उनके सामने रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी की गतिविधियों को और तेज करना होगा और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति के तहत काम करना होगा। इसके बिना चुनाव में सफलता हासिल करना मुश्किल है। उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को यह संदेश भी दिया कि संगठन में कमजोरियों की पहचान कर उन्हें सुधारना होगा और हर स्तर पर सक्रिय नेतृत्व बनाए रखना होगा। मायावती ने कहा कि हर विधानसभा सीट पर काम करना अनिवार्य है। प्रदेश की सभी विधानसभा

सीटों पर सक्रिय रहकर जनता से संपर्क बढ़ाना होगा। हर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी संभाल रहे बसपा नेता अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों तक पार्टी की योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी पहुंचाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता से सीधे संपर्क बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि पार्टी के पिछले कार्यों और आगामी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंच सके। यह कार्य केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को मजबूत करने और पार्टी को समाज में व्यापक रूप से स्थापित करने के लिए भी आवश्यक है। मायावती ने विपक्षी दलों की साजिशों की ओर भी ध्यान दिलाया। उनका कहना था कि विरोधी दल बसपा को कमजोर करने के लिए हर संभव हथकंडा अपनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यकर्ताओं को इन कोशिशों को समझना होगा और हर तरह के षड्यंत्र से सतर्क रहना होगा। पार्टी की मजबूती के लिए जरूरी है कि सभी सदस्य मिलकर विरोधी दलों की चालों का सामना करें और जनता को भ्रमित न होने दें। इसके लिए सभी को संगठन और जनाधार को मजबूत बनाने में जुट जाना

चाहिए। मायावती ने धर्म और जाति की राजनीति पर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि धर्म और जाति की राजनीति से समाज में नफरत और विभाजन फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से ब्राह्मण समुदाय की उपेक्षा की बात उठाई और कहा कि विरोधी दल ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देकर समाज में जहर घोल रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और इससे समाज में मेल-जोल और भाईचारे को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि समाज में फैलाई जा रही नफरत के खिलाफ सतर्क और जागरूक रहना बेहद जरूरी है। साथ ही, मायावती ने संसद में जारी गतिरोध पर भी नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना था कि सत्ता और विपक्ष मुठों पर चर्चा करने के बजाय एक-दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। संसद को चलाने के लिए जो कानून और नियम बनाए गए हैं, उन पर गंभीरता से अमल होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि टैरिफ, महंगाई और रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है, और इन पर चर्चा करने के बजाय राजनीतिक ड्रामा किया जा रहा है।



मथुरा में एक्सप्रेस-वे पर 6 की मौत, कंटेनर ने रौंदा

मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर स्लीपर बस से उतरकर खड़े यात्रियों को तेज रफ्तार कंटेनर ने रौंद दिया। हादसे में 6 की मौत पर मौत हो गई। एक गंभीर घायल है। घटना शनिवार तड़के 2.45 बजे की है। जानकारी के मुताबिक, बस दिल्ली के नागलोई से कानपुर देहात के रसूलाबाद जा रही थी। रास्ते में कुछ यात्रियों ने ड्राइवर को बाथरूम के लिए बस रोकने को कहा। ड्राइवर ने ग्रीन जोन की बजाय रास्ते में बस रोक दी। कुछ यात्री बस से उतरकर नीचे खड़े हो गए, तभी पीछे से आ रहे कंटेनर ने पहले बस को टक्कर मारी। फिर यात्रियों को रौंद दिया। कंटेनर का चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। हाईवे पर लार्शे बिछ गई कुछ यात्रियों के चहरे बुरी तरह कुचल गए। इससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। परिजनों ने स्वेटर-कपड़ों से उनकी पहचान की। मौके पर लंबा जाम लग गया। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एंबुलेंस से घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। इस बीच CM योगी ने हादसे का संज्ञान लिया। पीड़ित परिवारों को ढाढस बंधाया। हिम्मत रखने की अपील की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने और राहत कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। हादसा सुरीर थाना क्षेत्र में माइल स्टोन-88 के पास हुआ। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुई दुखद सड़क दुर्घटना के बाद जिला अस्पताल में भर्ती 1 घायल यात्री का हालचाल जाना। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिए कि घायल यात्री को हर सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

यूपी में 5 सीनियर IPS अफसरों के ट्रांसफर

यूपी में 5 सीनियर IPS अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। शासन ने शुक्रवार शाम ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी है। सभी DIG रैंक के अफसर हैं। इनमें से चार अफसरों को प्रमोशन के बाद अपनी पोस्टिंग का इंतजार था। आज उन्हें पोस्टिंग दे दी गई। सुशील कुमार घुले STF के DIG बनाए गए हैं। वे अभी तक STF में SSP थे। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेंट में DCP यमुना प्रसाद को मुरादाबाद PTS में DIG बनाया गया है। पुलिस मुख्यालय पर तैनात हेमराज मीणा को भी प्रमोशन के बाद पास्टिंग दे दी गई है, उन्हें CIFS में DIG बनाया गया है। मेरठ में 44वीं वाहिनी पीएसी में तैनात सचींद्र पटेल को लखनऊ में डीआईजी एंटी करप्शन में DIG के पद पर तैनाती दी गई है। यहां तैनात रहे अखिलेश चौरसिया को DIG स्थापना बनाया गया है। योगी सरकार ने 4 फरवरी की रात 24 IPS अफसरों के ट्रांसफर किए थे। इनमें 6 जिलों के वरिष्ठ SP भी शामिल रहे, जिन्हें प्रमोशन देकर DIG बनाया गया था। कुल 11 जिलों में SP और SSP बदले गए। सात साल आंखों के सर्जन रहे डॉक्टर कौस्तुभ को गोरखपुर का नया SSP बनाया गया। तेज-तर्रार महिला IPS चारु निगम को 2 साल बाद फील्ड में पोस्टिंग मिली। उन्हें सुल्तानपुर का SP बनाया गया है। 2024 में जब वह औरैया की SP थीं, तब वह तत्कालीन DM से भिड़ गई थीं। मामला लखनऊ तक पहुंचा तो उनका तबादला हो गया था। संभल में 100 करोड़ रुपये से अधिक का बीमा घोटाला पकड़ने वाली अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा का गौतमबुद्धनगर के लिए तबादला हुआ है। उन्हें अपर पुलिस उपायुक्त बनाकर भेजा गया है।

बेकाबू कार पलटी, मामा-भांजे समेत 3 की मौत



एटा में 100 की स्पीड में कार पेड़ से टकराकर पलट गई। तीन बार पलटी खाई, फिर सड़क से 15 फुट दूर गड्ढे में जा गिरी। हादसे में मामा-भांजे और एक युवती की मौत पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख-पुकार सुनकर राहगीर मौके पर दौड़े पहुंचे। उन्होंने आनन-फानन में कार का दरवाजा तोड़कर सभी घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और घायलों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। घटना से जुड़े वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें एक किशोर जमीन पर तड़पता हुआ दिखाई दे रहा है। कार सवार सभी लोग गुस्साम से मैनपुरी एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। हरियाणा नंबर की यह कार प्राइवेट कैब बताई जा रही है। पुलिस ने मृतकों के परिजन को सूचना दे दी है। मृतकों की पहचान मैनपुरी निवासी शिवम यादव (21), उनके मामा सुमित यादव (23) और गांव की रहने वाली मनकी (19) के रूप में हुई है। वहीं, मैनपुरी के ही रहने वाले राहुल (28) और खुशबू (22) घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शी शिव कुमार ने बताया, "मैं अपने गांव सकीट जा रहा था, तभी अचानक कार बेकाबू होकर पलट गई। इसके बाद मैंने चिल्लाकर स्थानीय लोगों को बुलाया। फिर कार में फसे लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन कार अंदर से लॉक थी। इसके बाद दरवाजा तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। इसमें 10 से 15 मिनट लग गए, लेकिन तब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस एंबुलेंस के साथ मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को वीरगंगा अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज भिजवाया।

देश में नंबर 1 जहां उत्तर प्रदेश लाइन वहीं से

प्रति वर्ष 400 लाख टन फल एवं सब्जियों का उत्पादन

गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू, शीरा उत्पादन में अग्रणी

करके दिखाए जो डबल इंजन सरकार है वो

UPGovtOfficial CMUttarpradesh CMOOfficeUP

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश